Title: Discussion on the motion for consideration of the State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2009 (Discussion not concluded and speech unfinished).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we go to item No. 16.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to move:

"That the Bill further to amend the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration."

The transfer of ownership of the State Bank of India (SBI) from the Reserve Bank of India (RBI) to the Central Government was carried out pursuant to the coming into force of the State Bank of India (Amendment) Act, 2007 (30 of 2007). There are certain provisions in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and the State Bank of Hyderabad Act, 1956 dealing with the approval of consultation with the RBI (in the capacity as owner of SBI) in the management and functioning of the Subsidiary Banks of SBI. Due to change in ownership, those provisions need to be suitably modified to reflect the change in ownership.

The Bill was introduced in the Lok Sabha on 12<sup>th</sup> December, 2009 and was referred to the Standing Committee on Finance. The Standing Committee had suggested two legislative amendments and the Government accepted both of them.

The first amendment recommended by the Standing Committee will enhance the ability of the Subsidiary Banks of the SBI to raise capital through rights issue. The second amendment suggested by the Standing Committee on Finance relates to substituting original heading of Section 63 relating to 'Power of the State Bank to make Regulations', with the word 'Power of the Subsidiary Banks to make Regulations'.

## MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion Moved:

"That the Bill further to amend the State Bank of Hyderabad Act, 1956, and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration."

श्री निशिकांत द्वे।

भी निश्वकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। कल जब वित्तमंत्री जी बोल रहे थे कि रिफॉर्म्स आपके हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। 28 फरवरी को वित्तमंत्री जी ने कहा कि-

"The financial sector reforms initiated during the early 1990s have borne good results for the Indian economy. The UPA Government is committed to take this process further. Accordingly, I propose to move the following legislations in the financial sector: 1) the Insurance laws; 2) the Life Insurance Corporation Bill; 3) Revised Pension Fund (Regulatory and Development) Authority Bill; 4) Banking Laws (Amendment) Bill; 5) Bill on the Factoring and Assignment of Receivables; 6) The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Bill, which we are discussing now, and 7) Bill to Amend RDBFI."

हमने जो प्रोरेस शुरू किया, हमारे घोषणा-पत् में जो है, उसको वे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपने कुछ बातें कहीं। महंगाई के बारे में जो डिस्कशन हुआ, मुझे काफी निराशा हुई। माननीय यशवंत जी ने जो बातें कहीं थीं और माननीय वित्तमंत्री जी ने उनका जो जवाब दिया था, उससे काफी निराशा हुई। निराशा स्वासकर तब हुई जबिक उधर से माननीय सत्तमान खुर्शीद साहब, यदि वे यहां होते तो मैं उनसे पूछने वाता था, उन्होंने दीवार फिल्म के डायलॉग द्वारा कहा कि आपके पास माँ नहीं हैं तो हमारे पास मनमोहन सिंह जी हैं। मैं मानता हूँ कि आपके पास मनमोहन सिंह जी हैं, श्री मोंटेक सिंह अहत्वातिया हैं, श्री सी. रंगराजन हैं, श्री कौंशिक बसु हैं, श्री सैम पित्रोदा हैं और सबके गुरू माननीय वित्तमंत्री पूणब मुखर्जी जी हैं। सन् 1972 में जब ये वित्तमंत्री बने थे, बाकी सब कहीं नहीं थे। मुझे तगता है कि गुरू गुड़ हो गया है और वेता वीनी हो गया है। इस सरकार में इतने अर्थशास्त्री हो गए हैं कि एक कहावत हैं - ज्यादा जोगी, मठ उजाड़। हितोपदेश की एक कहानी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ किताब देखते हैं। किताब देखने के बाद सॉल्युशन निकालने की कोशिश करते हैं।

हितोपदेश में अलोकिका पण्डिता की एक कहानी है जिसमें चार लड़के पढ़ने जाते हैं। वे पढ़ने के बाद, माननीय पूधानमंत्री जी की तरह अर्थशास्त्री हो जाते हैं। जब वे पढ़कर आते हैं, तो एक चौराहे पर भटक जाते हैं। भटकने के बाद उनको घर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। वे किताब निकालते हैं, उसमें उन्हें दिखाई देता है - महाजनो येन गता सो पन्था। उनको दिखाई देता है कि बड़े लोग जिस रास्ते से गए, वही रास्ता सही हैं। वे लोग उस रास्ते पर देखते हैं कि कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे हैं, वे उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं और श्मशान पढ़ंच जाते हैं। श्मशान में उनको और कोई नहीं बल्कि गधा दिखाई देता है। गधा देखकर वे उससे लिपटने लगते हैं क्योंकि वे फिर से किताब निकाल कर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि - राजद्वारे श्मशाने ज्यौ, यश तिष्ठित सौ बानधवा:। उनको लगता है कि श्मशान में खड़ा यह गधा ही हमारा भाई है। इसके बाद उन्हें ऊँट दौड़ कर आता दिखाई देता है तो उनको लगता है कि धर्मम् तीवृम् गतिम्। उनको लगता है कि धर्म बड़ी तेजी से चल रहा है, यह ऊँट चूंकि बड़ी तेजी से भाग रहा है तो यह धर्म हैं। फिर वे लोग गधा और ऊँट को बांध देते हैं। जब गधा वाला उसको मारता है तो वे उसके आगे चले जाते हैं। आगे उनको एक नदी मिलती है, फिर उनको रामझ में नहीं आता है कि इस नदी में क्या होगा?

एक पत्ते के सहारे वे नदी क्रास करना चाहते हैं। वे फिर से अपनी किताब निकालते हैं और देखते हैं कि दो आदमी डूब रहे हैं, दो आदमी बच रहे हैं तो वे किताब में देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्याज्यित पाण्डित्यः। उन्हें लगता है कि ये दो आदमी तो डूब रहे हैं, इन्हें छोड़ दो, आधे दो आदमी तो हम बच रहे हैं। जब वे उसके आगे एक गांव में जाते हैं तो कोई उन्हें सेंबई खिलाता है तो उन्हें किताब में लिखा दिखाई देता है कि दीर्घसूत्री विनश्यित। उन्हें लगता है कि जो लंबी-लंबी चीज है, वह विनाश का कारण है, इसलिए सेंबई नहीं खानी चाहिए। मेरा यह कहना है कि जितने भी अर्थशास्त्री सरकार में हैं, उन्हें चीजें दिखाई नहीं रही हैं।

यशवंत शिन्हा जी ने महंगाई के बारे में बोलते हुए सरकार से पूछा कि एफडीआई एंड रिटेल के बारे में जवाब दीजिये। सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरा एक ही सवाल है, आप रोजगार पर मत जाड़ये, इम लोग गांव से आते हैं। पहले एक आजीविका का साधन होता था। यदि यहां शहर के लोग भी हमारी बात सून रहे होंगे, आजीविका का एक साधन होता था कि लोग गाय-भैंस पालते थे<sub>।</sub> गाय-भैंस का दूध बेचते थे और उसी से उनका पूरा परिवार चलता था<sub>।</sub> आज आप बताइचे कि मदर डेयरी आने के बाद कितने लोग गाय और भैंस पोस रहे हैं। उनकी आजीविका का साधन क्या होगा? यदि आप वालमार्ट ले आयेंगे, किंगफिशर ले आयेंगे, टेस्को ले आयेंगे, बडी-बडी कंपनियां ले आयेंगे तो लोगों के रोजगार का क्या होगा? आपने इसका भी जवाब नहीं दिया। हमने आपसे पूछा कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बंद कीजिये, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने उस एफएमसी का जवाब नहीं दिया। आप हम लोगों को आंकड़ों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। निपटी से आम आदमी को क्या मतलब हैं? आप इंपलेशन रेट की बात कर रहे हैं कि इस बार इंपलेशन रेट 9 परसेंट हैं। इंपलेशन रेट वर्ष 2008-09 के आधार पर है या वर्ष 2010-11 के आधार पर हैं। वर्ष 2008-09 में जितना प्रोडक्शन हुआ था, आज आपका प्रोडक्शन उससे ज्यादा हैं। चाहे गेहूं का प्रोडक्शन ते तीजिये, चाहे चावल का ते तीजिये, शुगर का ले लीजिये, मस्टर्ड ऑयल का ले लीजिये, किसी का भी प्रोडवंशन ले लीजिये<sub>।</sub> क्या हम उस रेट पर जा पाये हैं? आप इंप्लेशन प्ले करते हैं कि वर्ष 2011 में यह रेट था तो उसके आधार पर केवल 9 परसेंट इंकीज हुआ हैं। लोगों को जीडीपी नहीं पता हैं, लोगों को इंप्लेशन नहीं पता हैं, लोगों को यह पता हैं कि वर्ष 2008 में हम 12 रूपये किलो चावल खा रहे थे और आज 20 रूपये किलो चावल खा रहे हैं और 20 रूपये से रेट नीचे नहीं जा रहा है| आप आंकड़ों में इंप्लेशन की बात कर सकते हैं| आप आम लोगों के लिए कौन सा विषय लेकर आये और मुझे बड़ी निराशा होगी क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जब बोलते हैं तो मैं उनका बड़ा आदर करता हुं। उन्होंने गो का जिस ढंग से जवाब दिया, वह मेरे लिए बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा कि मैं भटक गया हूं और वे लोकपाल पर आ गये। मैं यह कह रहा हूं कि जिस रिफॉर्म्स पर आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की बात कर रहे हैं, हम आपको सहयोग देने की बात कर रहे हैं। आज लोकपाल पर यह सरकार गड़बड़ा रही हैं, गर्मा रही हैं, अन्ना हजारे को किसने पैदा किया? अन्ना हजारे, मैं हुरियत से उसकी तुलना करता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी का मुदा था<sub>।</sub> हम लोकपाल की बात कर रहे थे। यह ठीक हैं कि वर्ष 2002 में आपने, कमेटी ने इसे दिया और हम लोकपाल को नहीं ला पाये। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या आप भारतीय जनता पार्टी से बात करने आये? आप बात करने नहीं आये। आपने अन्ना हजारे को बुलाकर बात की, अन्ना हजारे को आपने नेता बनाया और उसकी वही दुगर्ति होनी थी, जो आज दुगर्ति हो रही हैं। इस पार्लियामेंट की मौकली हो रही हैं और उसके दोषी केवल आप और आप हैंं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 के अपने इतेवशन मैनीफेस्टो में काले धन की बात कही थी, हमने काले धन की बात कही थी। आपने हमसे बात नहीं की और आपने बाबा रामदेव को एयरपोर्ट पर वेलकम दिया। यदि आप बाबा रामदेव से मिलेंगे, आप अन्ना हजारे से मिलेंगे, यदि आप भारतीय जनता पार्टी को या इस प्रिंसिपल अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, इस संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यही हाल होगा जो आज हो रहा हैं|...(<u>व्यवधान</u>)मैं बिल पर ही आ रहा हूं<sub>|</sub> चूंकि कल बोलते-बोलते वे भी उस पर बोले थे<sub>|</sub>...(<u>व्यवधान</u>)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय से भटक गये हैं।

**भी निभिक्तांत दुबे :** महोदय, मैंने स्वयं कहा है कि मैं भटक गया हूं<sub>।</sub> अब मैं बिल पर आ रहा हूं<sub>।</sub>...(<u>व्यवधान</u>) आप बिल पर सुनना चाहते हैं तो बिल पर सुनिये<sub>।</sub>...(<u>व्यवधान</u>)

**शी महेश जोशी (जयपुर):** अन्ना हजारे तो कहते हैं कि मेरा एकाउन्ट ही नहीं हैं<sub>।</sub>...(<u>व्यवधान)</u> आप उन्हें बहस में लेकर आ रहे हैंं।...(<u>व्यवधान)</u>

श्री **निशकांत दुबे :** आप मेरी बात सुनिये<sub>।</sub> अभी लेपट के हमारे साथी ने कहा कि बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन की ऑल इंडिया स्ट्राइक हैं<sub>।</sub> अब मैं बैंक पर ही आ रहा हूं।...(<u>व्यवधान</u>)

15.25 hrs.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

बैंक स्ट्राइक पर हैं| वे क्यों स्ट्राइक पर हैं? ओईसीडी की रिपोर्ट हैं, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूडिड हैं| वह यह कहता हैं कि:

"The Organisation for Economic Co-operation and Development has presented its Report on Indian Economic Survey and has recommended among other things wide-ranging financial sector reforms to be implemented"

वह आगे कहता है कि :

"The Report has recommended speeding of financial sector reforms and privatisation of public sector banks by reducing the Government capital to 33 per cent and thus increase private shareholding to 67 per cent."

आप जो अमैन्डमैंट ला रहे हैं, आप जो बैंकिंग रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसमें से जो ओएनसीडी की रिपोर्ट हैं जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हैं, वह कहीं न कहीं खतरा बता रही हैं और इसके कारण इस देश में जो खतरा मँडरा रहा हैं, उसके कारण बैंक इंप्लॉइज़ स्ट्राइक पर हैं। जो स्पुरामराजन कमेटी की रिकमंडेशन हैं, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं और जो खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट हैं, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, यह जवाब आपको देना चाहिए। इसके बाद हमारे कुछ पूष्त हैं। हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे कुछ पूष्त हैं।

Question No. 1- Certain amendments were made in the year 2007, as per the recommendation of the Standing Committee on Finance, which examined the SBI Subsidiary Laws, 2006. Why have these amendments not been implemented?

Question No. 2 – Can the State Bank of India take over the business of its own subsidiaries under Section 35 of the SBI Act without seeking the approval of the Parliament?

Question No. 3- What are the reasons for increase in NPAs? आज आपने खुद जवाब दिया है कि एनपीएज़ भी इनकीज़ हो रहा है। How good is the performance of the subsidiary banks in the area of Credit Deposit Ratio, CRR, operating margins and achievements in the financial inclusion? How autonomous are the subsidiary banks, whether it is practicable for the Chairman of the SBI to attend the Board meeting of the subsidiary bank?

Question No.4- What are the effects on SBI after merger of subsidiary banks; pre and post merger on performance parameters? What is the economic justification for the merger of banks in general and that of subsidiary bank of the SBI? What is the Government policy on consolidation in the banking industry? How will it be managed when the SBI itself is not managed properly?

Question No. 5- What is the experience of SBI with regard to merger of State Bank of Saurashtra and State Bank of Indore. Why is the merger of one or two subsidiary banks with SBI was taken earlier, not this time?

Question No. 6- What shall be the difference between autonomy be given to the subsidiary banks and the autonomy of the nationalised banks? What will be the consequences of giving autonomy to subsidiary banks to frame their own rules?

Question No. 7- Why is that the NPAs of the subsidiary banks are larger than their profits?

Question No. 8- Please provide the data on NPA and wilful defaulters. Has SBI given adequate attention to the national priorities?

Question No. 9- What are the salient features of the long-term vision / strategy papers submitted by SBI to the Government and whether the Government has given any response to this paper? If not, state the reason.

Question No. 10- What is the economic justification in integrating the subsidiary banks with the State Bank of India? The increasing NPAs of SBI indicate mismanagement. When the NPAs of the subsidiary banks are also increasing, why is the decision taken to integrate the subsidiary banks and how will the increasing NPA to be managed? Will it not complicate the problem of management of NPAs?

Question No. 11- Merger will complicate the promotion avenues and the industrial relations. The employees of the State Bank of Indore have been stubbornly opposing the integration. So, in spite of the Employees' opinion and administration and problem of mismanagement of NPAs, why is the Government ignoring this and allowing merger of subsidiary banks with the SBI?

Question No. 12- Does the Government want to disinvest a part of its share, that is being acquired from RBI for raising revenue? Further, what is the present shareholding of the Government in SBI? What is the present shareholding of the Government in SBI?

Question No. 13- How have the benefits of the employees being affected after the merger? Has SBI thought about the deployment of the staff of the merged subsidiaries?

Question No. 14- I would like to know whether the Chairman of SBI also being the Chairman of subsidiary banks is

present in the board meetings of all the subsidiaries.

Question No. 15- It may be explained as to how the State Bank of Hyderabad has been making profit in spite of rise in NPAs.

Question No. 16- It may be explained whether any assessment has been done about regulatory capital requirements of subsidiary banks. If so, had they been found self-sufficient? If not, I would like to know whether SBI seeks to infuse capital into these banks. The Government is requested to furnish a copy of the Assessment Report.

MADAM CHAIRMAN: Nishikantji, now it is 3.30 p.m. and we have to take up Private Members' Business. You may continue next time.